1.76 लाख रीजनल सर्विस प्रोवाइडर (आरएसपी) हैं रेलवे के देशभर में, जो लोगों को टिकट मुहैया कराते हैं। इनमें से कई गोरखधंधे में लगे हैं। फर्जी मेल आइडी के अलावा वह मिर्ची और एनएमएस जैसे साफ्टवेयर का भी प्रयोग करते हैं।

शांति व समृद्धि के लिए मिलकर काम करेंगे भारत और जापान

मजबूत रिश्ते ▸ प्रधानमंत्री मोदी ने की जापान के पीएम एबी शिंजो से मुलाकात

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर हुई चर्चा

बैंकाक, प्रेट्र : हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए भारत और जापान मिलकर काम करेंगे। क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो की मुलाकात में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा हालात की समीक्षा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई।

आसियान देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने थाइलैंड की राजधानी बैंकाक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एबी शिंजो संग द्विपक्षीय बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की सेना के तेजी से पैर पसारने और बढ़ते आर्थिक दबदबे का मुद्दा बैठक के दौरान प्रमुखता से उठा। विदेश मंत्रालय ने बताया, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अन्य देशों में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई।' मोदी और एबी ने स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की दिशा में काम करने का संकल्प ऐसे समय में लिया है, जब क्षेत्र की समुद्री सीमाओं में चीन के बढ़ते दखल को लेकर आसियान के कई सदस्य देशों के बीच चिंता बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने इस महीने के अंत में भारत और जापान के विदेश तथा रक्षा मंत्रियों के बीच भारत में होने वाली 'टू प्लस टू' वार्ता के बारे में भी बात की।

बैंकाक में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो एबी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। एएनआइ

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'अपने मित्र प्रधानमंत्री एबी से मिलना हमेशा शानदार रहा है। आज हमारी मुलाकात बहुत अच्छी थी। हमने अपने देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने सहित कई विषयों पर विमर्श किया।' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि दोनों नेताओं ने भारत-जापान 'टू प्लस टू' वार्ता और वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आधार तैयार किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अगले महीने होने वाले वार्षिक भारत-जापान शिखर सम्मेलन के लिए जापान के प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर वह उत्सुक हैं। मोदी ने भरोसा जताया कि आगामी शिखर सम्मेलन सफल होगा और इससे भारत व जापान के बीच विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी और गहरी होगी। पिछले चार महीनों में मोदी और एबी की यह तीसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेता सितंबर में रूस के व्लादिवोस्तोक में मिले थे। बैठक में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी हुई।

आतंकी समूहों के खिलाफ म्यांमार का सहयोग अहम : आसियान सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से भी मुलाकात की। मोदी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं को विस्तार देने की भारत की तैयारी की जानकारी दी। साथ ही भारत-म्यांमार सीमा पर सक्रिय आतंकी समूहों से निपटने की दिशा में म्यांमार के सहयोग की जरूरत पर भी जोर दिया।

अमेरिका-आसियान बैठक से नदारद रहे शीर्ष नेता : आसियान की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नहीं आने के बाद आसियान देशों के कई नेता सोमवार को अमेरिकी अधिकारियों संग हुई बैठक से दूर रहे। आसियान देशों से केवल थाइलैंड, वियतनाम और लाओस के प्रमुख और कुछ विदेश मंत्री ही बैठक में आए। अमेरिका की ओर से आसियान सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन शामिल हुए। इस रवैये के बाद अमेरिका पर दक्षिण एशियाई देशों की अनदेखी का भी आरोप लग रहा है। हालांकि ब्रायन ने इस बात का खंडन किया और कहा कि अमेरिका अपने दक्षिण एशियाई सहयोगियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आसियान 10 देशों का समूह है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं।

आरसेप पर हस्ताक्षर नहीं करना मोदी के मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है : शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि आरसेप समझौते पर भारत के हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। एक के बाद एक किए ट्वीट में शाह ने कहा कि इस फैसले से भारत के किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र, डेयरी और विनिर्माण क्षेत्रों को सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा, 'आरसेप पर हस्ताक्षर न करने का भारत का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प का परिणाम है।'

गृह मंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्षों से यह कड़ा रुख रहा है कि अगर हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो हम समझौता नहीं करेंगे और यह अतीत की तुलना में स्वागत योग्य कदम है जब कमजोर संप्रग सरकार व्यापार के मुद्दे पर झुक गई थी और राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकी।'

भाजपा का राहुल पर तंज : वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आरसेप के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की आलोचना किए जाने पर पलटवार किया है। भाजपा ने ट्वीट किया, 'प्रिय राहुल गांधी, लगता है ध्यान यात्रा ने आपको आरसेप पर जगा दिया है।' भाजपा ने कहा, 'कुछ तथ्य दिए जा रहे हैं जो आपकी चयनात्मक भूलने की बीमारी में मदद करेंगे।' सत्तारूढ़ दल ने कहा कि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार थी, जो 2012 में आरसेप वार्ता में शामिल हुई थी।

सज्जन कुमार की जमानत अर्जी पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

▸ सिख विरोधी दंगों में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई है सजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर विचार करने के लिए सोमवार को तैयार हो गया। सज्जन कुमार ने शीर्ष अदालत से जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाली पीठ ने सज्जन कुमार के वकील शेखर नफाड़े की उस दलील का संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, हम इस पर गौर करेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उनकी अपील लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत दी जाए। हाई कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार (73) ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वह फिलहाल जेल में हैं। सज्जन कुमार को 1984 में एक-दो नवंबर को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के राजनगर-एक में सिख समुदाय के पांच लोगों की हत्या और राजनगर-दो में एक गुरुद्वारे को जलाए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया था।

सज्जन कुमार फाइल फोटो

पैरोल मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने विकास से कहा, सजा पूरी करो

नीतीश कटारा हत्याकांड

▸ शीर्ष अदालत ने चार हफ्ते की पैरोल मांगने वाली याचिका खारिज की

▸ 25 साल कैद की सजा काट रहा है बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल कैद की सजा काट रहे विकास यादव के पैरोल मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अपनी सजा पूरी करो। शीर्ष अदालत ने पैरोल देने से इन्कार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। नीतीश कटारा की 2002 में हत्या कर दी गई थी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने चार सप्ताह का पैरोल मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए यादव से कहा, 'आपको 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है, इसे पूरी करो।' इस बीच, पीठ ने यादव की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने बिना किसी राहत के 25 साल कैद की सजा सुनाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।

विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को कटारा के अपहरण और हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2002 में 16 और 17 फरवरी की रात अपहरण के बाद कटारा की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को विकास की बहन भारती से कटारा के कथित प्रेम संबंधों के चलते अंजाम दिया गया था जो अलग-अलग जाति से थे। इस हत्याकांड के तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। विकास यादव ने मामले में विभिन्न आधारों पर पैरोल मांगा था और कहा था कि मामले में वह पहले ही 17 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुका है।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

अयोग्यता मामले में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड में ली जाए : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्नाटक कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया किया कि वह प्रदेश के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आडियो क्लिप को रिकार्ड पर ले। इस क्लिप में येदियुरप्पा बागी विधायकों के त्याग का जिक्र करते हुए कथित रूप से पार्टी के नेताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं, जिनकी वजह से भाजपा की सरकार बन पाई है।

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, वह कांग्रेस की ओर से पेश नवीन सामग्री पर विचार के लिए पीठ गठन के बारे में सीजेआइ रंजन गोगोई से बात करेगी। येदियुरप्पा का वह कथित ऑडियो क्लिप शुक्रवार को सामने आया था जिसमें वह पार्टी के उन नेताओं के प्रति नाराजगी जता रहे थे जो अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस-जद (एस) के विधायकों को पांच दिसंबर को 15 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए टिकट देने का विरोध कर रहे थे।

अयोग्य घोषित किए गए 17 में से 15 विधायकों की सीटों पर पांच दिसंबर को उपचुनाव होगा। इन विधायकों के त्यागपत्र और विश्वास मत के दौरान सदन से अनुपस्थित रहने की वजह से कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन सरकार गिर गई और येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्ता में आई।

मंदी और बेरोजगारी के खिलाफ संसद से सड़क तक संग्राम करेगा विपक्ष

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ कांग्रेस की अगुआई वाली बैठक से राकांपा लापता, तृणमूल की सांकेतिक भागीदारी

▸ वाट्सएप जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच की मांग पर राष्ट्रपति को ज्ञापन देगा विपक्ष

विपक्षी पार्टियां आर्थिक मंदी और बढ़ती बेरोजगारी से लेकर किसानों की खराब हालत के मुद्दों पर संसद से सड़क तक सरकार की घेराबंदी करेंगी। वहीं वाट्सएप जासूसी कांड पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने के लिए विपक्षी दल राष्ट्रपति को संयुक्त ज्ञापन सौंपेंगे। विपक्षी दलों ने सरकार पर पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस की अगुआई में 13 विपक्षी दलों की हुई बैठक में सरकार के खिलाफ संग्राम के इन मुद्दों पर सहमति बनी। हालांकि विपक्षी दलों की इस बैठक में राकांपा शामिल नहीं हुई तो तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना एक नुमाइंदा भेजकर केवल सांकेतिक मौजूदगी ही दर्ज कराई। जबकि आम आदमी पार्टी को आमंत्रित की नहीं किया गया था।

कांग्रेस की पहल पर हुई इस बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने की। बैठक में द्रमुक, राजद, तृणमूल कांग्रेस, जदएस, आरएलएसपी, माकपा, भाकपा, आरएसपी, आइयूएमएल, केरल कांग्रेस और एलजेडी के नेता शामिल हुए। सपा और बसपा तो पहले से ही विपक्षी खेमे की बैठकों से दूरी बना ली है।

बैठक के बाद विपक्षी नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। जीडीपी छह साल के निचले स्तर पर है तो उद्योग, निर्यात, कारोबार से लेकर बाजार सभी जगह आर्थिक मंदी का असर है। किसानों को एमएसपी से भी काफी कम दाम मिल रहा है और उनकी हालत बदतर है। इन सब वजहों से बेरोजगारी भी 50 साल के सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। इन मुद्दों पर पांच से 15 नवंबर तक सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर रखी है।

नई दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस दौरान द्रमुक नेता टीआर बालू, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, रालोद नेता अजीत सिंह और एलजेडी नेता शरद यादव। प्रेट्र

विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर संसद के भीतर ही नहीं बाहर भी सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए साझा रणनीति पर सहमति जताई है। मुक्त व्यापार समझौते आरसेप के खिलाफ भी विपक्षी दल मुखर आवाज उठाएंगे। मोदी सरकार को बीते 70 साल की सबसे असंवेदनशील सरकार करार देते हुए आजाद ने कहा कि देश ने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी जिसे जनता के तकलीफों की परवाह ही नहीं है।

वाट्सएप जासूसी कांड को लेकर विपक्ष का रुख पूछे जाने पर आजाद ने कहा कि इस बैठक में इसको लेकर चर्चा नहीं की गई। चूंकि यह आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित बैठक थी इसीलिए तय हुआ कि जासूसी कांड पर विपक्षी दल अलग से मंत्रणा कर जल्द ही साझा रणनीति तय करेंगे। लेकिन, बैठक में शामिल एक विपक्षी नेता ने बताया कि जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संयुक्त ज्ञापन देने पर विपक्षी दलों में सैद्धांतिक सहमति बनी है।

द्रमुक नेता टीआर बालू ने कहा कि आर्थिक हालत इतने चिंताजनक हैं कि प्रधानमंत्री को विदेश भ्रमण छोड़ स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव ने दिखाया है कि जनता आगे बढ़ चुकी है और अब विपक्षी दलों को उनके पीछे लगकर संसद से सड़क तक इस सरकार के खिलाफ संग्राम में उतरना है। वामपंथी दल बैठक में तो मौजूद थे मगर संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में शामिल नहीं हुए।

13 दलों की बैठक में शामिल नेता : बैठक में कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, राजीव शुक्ल, रणदीप सुरजेवाला, द्रमुक के टीआर बालू, एलजेडी के शरद यादव, राजद के मनोज झा शामिल हुए। इनके अलावा आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, रालोद के अजीत सिंह, तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक, जदएस की तरफ से डी कुपेंद्र रेड्डी, माकपा से टीके रंगराजन, भाकपा के डी राजा, विनय विश्वम, आरएसपी के शत्रुजीत सिंह, आइयूएमएल के पीके कुन्हलकुट्टी और केसीएम के जोस के मणि भी बैठक में मौजूद रहे।

आरसेप से भारत के बाहर रहने को कांग्रेस ने बताई अपनी जीत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) मुक्त व्यापार समझौते में शामिल नहीं होने के भारत के फैसले को राष्ट्रहित के लिए संघर्ष करने वाले सभी ताकतों की जीत करार दिया है। साथ ही पार्टी ने इसका श्रेय लेते हुए साफ कर दिया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के तगड़े विरोध ने भाजपा सरकार को आरसेप समझौते से पीछे हटने के लिए बाध्य किया है।

भारत के अपने हितों के मद्देनजर आरसेप में शामिल नहीं होने के ऐलान के तुरंत बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए पार्टी की यह प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ताकतवर विरोध के चलते किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, छोटे और बड़े व्यवसायों के हितों पर प्रहार के लिए आगे बढ़ी सरकार को अपने कदम रोकने पड़े हैं।

रणदीप सुरजेवाला फाइल फोटो

पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि भयंकर बेरोजगारी, डूबती अर्थव्यवस्था, खेती के संकट और आर्थिक कुप्रबंधन के इस दौर में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) भारत के लिए बड़ी विपदा होने वाला था। इससे समझौते का हिस्सा बनते ही भारत सस्ते चीनी वस्तुओं का डंपिंग बाजार बन जाता और देशी उद्योग व कारोबार बर्बाद हो जाते।

'भारत से अरबों डॉलर के रक्षा सौदों पर वार्ता जारी'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में दी है जानकारी

▸ अमेरिका से 16 अरब डॉलर के रक्षा उपकरणों की खरीद कर चुका है भारत

अमेरिका धीरे-धीरे भारत को रक्षा उपकरणों व इससे जुड़े तमाम उत्पादों की आपूर्ति करने वाले देश के तौर पर स्थापित होता जा रहा है। भारत एक दशक पहले तक अमेरिका से किसी भी तरह के रक्षा उत्पादों को नहीं खरीदता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत 16 अरब डॉलर के रक्षा उपकरणों का आयात अमेरिका से कर चुका है। साथ ही आने वाले दिनों में अतिरिक्त अरबों डॉलर के रक्षा उपकरणों की खरीद की बातचीत जारी है। इस बात अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से सोमवार को हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जारी रिपोर्ट में हुई है। यह रिपोर्ट तब जारी हुई है जब बैंकाक में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण देशों की बैठक चल रही है।

'मुक्त व खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र' नाम की इस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि जब से भारत व अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता की शुरुआत हुई है, तब से आर्थिक व रक्षा संबंधों में काफी मजबूती आई है। सनद रहे कि टू प्लस टू वार्ता के तहत दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसकी एक बैठक वर्ष 2018 में हुई थी और अगली बैठक इसी महीने संभावित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक प्रमुख रक्षा सहयोगी के तौर पर भारत ने अमेरिका से 16 अरब डॉलर के हथियारों की खरीद की है और अरबों डॉलर की खरीद की बात हो रही है। उसने यह भी बताया है कि नवंबर, 2019 में दोनों देशों के बीच पहली बार तीनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होने वाला है। इसमें भारत, आस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच बढ़ रहे रक्षा सामंजस्य का भी जिक्र किया गया है। इन चारों देशों के बीच पहली मंत्रिस्तरीय बैठक सितंबर, 2019 में की गई है।

रिपोर्ट में भारत के साथ बढ़ते ऊर्जा सहयोग को लेकर भी महत्व दिया गया है। जिस तरह से भारत कुछ वर्ष पहले तक अमेरिका से कोई रक्षा उपकरण नहीं खरीदता था, उसी तरह से भारत पहले ऊर्जा की खरीद भी नहीं करता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वर्ष 2018 में भारत ने अमेरिका से 6.2 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पादों की खरीद की है। यह सौदा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। हाल ही में संपन्न पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ऊर्जा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करने जा रहा है।

चिदंबरम ने ईडी के आरोपों को बताया बेबुनियाद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सोमवार को न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण पीठ ने सुनवाई को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

इस मामले में ईडी ने कहा था कि व्यक्तिगत हित और भ्रष्टाचार के लिए पी चिदंबरम ने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ मिलकर साजिश रची थी और पद का दुरुपयोग करते हुए आइएनएक्स मीडिया को विदेशी संवर्धन निवेश बोर्ड की मंजूरी दिलाई थी। पीठ के समक्ष दाखिल जवाब में चिदंबरम ने कहा कि ऐसे कोई सुबूत पेश नहीं किए गए जिनसे उन पर आरोप साबित हो सकें।

'गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों पर लगाम जरूरी'

▸ वाट्सएप जासूसी कांड की जांच कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार : पई

बेंगलुरु, प्रेट्र : सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विशेषज्ञ टीवी मोहनदास पई ने सोमवार को कहा कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों ने बाजार पर कब्जा जमा लिया है और अब समय आ गया है कि दुनिया भर में सरकारें इन पर लगाम लगाएं। इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने यह भी कहा कि सरकार को वाट्सएप जासूसी कांड की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए।

पई ने कहा कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफार्म ने बाजार पर एकाधिकार कर लिया है। वो जो कुछ भी हो रहा है उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। ये कंपनियां वैश्विक स्तर पर लोगों के दिमाग पर भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रही हैं। इनसे निपटने के लिए मानक बनाए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने सूचनाओं का भंडारण कर रखा है। इन्हें हम सभी को बताना चाहिए कि वो इन सूचनाओं को मालवेयर या अन्य किसी टेक्नोलॉजी से किसी तरह सुरक्षा करेंगी, ताकि हमारी जासूसी ना हो सके।

मोहनदास पई फाइल फोटो

पई ने कहा कि इन प्लेटफार्म पर असीमित डाटा मौजूद है। इसके माध्यम से ये कंपनियां लोगों की आदतों और उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में पता लगा रही हैं। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है।

उन्होंने कहा कि ये कंपनियां उपयोगकर्ताओं के साथ कांट्रैक्ट (अनुबंध) करती हैं, लेकिन कांट्रैक्ट के जरिए निजता की सुरक्षा नहीं की जा सकती। इनका कांट्रैक्ट भी एकतरफा होता है, वो आप पर नियंत्रण कर लेती हैं और आप पर अपना प्रभाव जमा लेती हैं।

वाट्सएप जासूसी कांड की जांच के लिए एसआइटी बनाने की मांग

मुंबई, प्रेट्र : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने वाट्सएप जासूसी कांड की जांच के लिए एसआइटी गठित करने की मांग की है। उन्होंने इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर वाट्सएप के जरिए लोगों की जासूसी कराए जाने के मामले पर केंद्र सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की।

अनदेखी की सजा

रेलवे ने देशव्यापी छापेमारी में 11 हजार लोगों के 2801 कंफर्म टिकट रद किए, रेलवे के 59 एजेंट ब्लैक लिस्ट, 528 दलाल गिरफ्तार किए गए

फर्जी आइडी वाले टिकट से सफर में लगा अड़ंगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे की लापरवाही से हजारों यात्री कंफर्म टिकट के बावजूद इस बार अपने घर जाकर दीवाली और छठ नहीं मना पाए। इन लोगों का दोष मात्र इतना था कि इन्होंने आइआरसीटीसी के एजेंट से केवल उनके वास्तविक मेल आइडी का उपयोग करने का अनुरोध नहीं किया था। नतीजतन एजेंट ने फर्जी मेल आइडी से इनका टिकट बुक करा दिया, लेकिन आरपीएफ ने छापेमारी कर ऐसे सभी टिकटों को अवैध घोषित कर ब्लॉक करा दिया। इस कवायद के बावजूद हजारों लोग इसी प्रकार के टिकटों पर यात्रा करने में सफल रहे और आरपीएफ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई।

देश में फर्जी मेल आइडी के जरिये रेलवे टिकटों की बुकिंग का धंधा जोरशोर से चल रहा है। इसे रोकने के लिए आइआरसीटीसी, क्रिस, कामर्शियल विभाग तथा आरपीएफ के अधिकारियों की टीम मिलकर प्रयास कर रही है। पिछले दिनों इस टीम ने आइआरसीटीसी द्वारा नियुक्त प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडरों, रीजनल सर्विस प्रोवाइडरों के अलावा व्यक्तिगत दलालों के यहां छापे डाले, जिससे इनके देशव्यापी नेटवर्क का पता चला है।

ये भोलेभाले लोगों को कंफर्म टिकट प्रदान करने के लिए उनकी फर्जी मेल आइडी बनाते और प्रयोग करते हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए आरपीएफ ने एक मेल आइडी से तीन माह में 14 से अधिक टिकट बुक कराने वालों की धरपकड़ शुरू की। 26 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चले अभियान में फर्जी आइडी पर बुक 28,01 कंफर्म टिकट ब्लॉक कराए गए। इससे 11 हजार से ज्यादा लोगों का न सिर्फ पैसा बर्बाद हुआ, बल्कि वे दीवाली और छठ मनाने अपने घर भी नहीं जा पाए। हालांकि इसी प्रकार के 15,426 टिकट वाले 60 हजार से ज्यादा लोगों को यात्रा करने से रेलवे नहीं रोक पाई। हालांकि इनके एजेंट आरपीएफ के शिकंजे में आ गए हैं। इन्होंने बुकिंग के लिए 2720 मेल आइडी का इस्तेमाल किया था।

प्रतीकात्मक फोटो

देश में 1.76 लाख आरएसपी, कई गोरखधंधे में लगे

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि देश में 1.76 लाख रीजनल सर्विस प्रोवाइडर (आरएसपी) हैं। इनमें से कई इस गोरखधंधे में लगे हैं। फर्जी मेल आइडी के अलावा मिर्ची और एनएमएस जैसे साफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। एजेंट से टिकट बुक कराते वक्त उन्हें ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनका टिकट उनके द्वारा प्रदत्त मेल आइडी से ही बुक कराया जाए। छापेमारी के 519 मामलों में 528 व्यक्तिगत एजेंट गिरफ्तार किए गए, जबकि 37 फरार हो गए हैं। इस दौरान गड़बड़ी में शामिल 65 आरएसपी की पहचान की गई है। जिसमें से 59 को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इनमें 17 उत्तर रेलवे व 13 उत्तर-मध्य रेलवे के हैं।

मिर्ची मामले में बिंद्रा की जमानत अर्जी पर ईडी ने दाखिल किया जवाब

मुंबई, एएनआइ : गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथ कथित लेनदेन में गिरफ्तार रंजीत सिंह बिंद्रा की जमानत अर्जी पर ईडी ने सोमवार को जवाब दाखिल कर दिया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 अक्टूबर को बिंद्रा को गिरफ्तार किया था और विशेष अदालत से उसकी हिरासत मांगी थी। इसके बाद बिंद्रा को सात नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मिर्ची को मुंबई में संपत्ति कब्जाने में बिंद्रा ने जहां कथित तौर पर मदद की थी वहीं रियल इस्टेट से उसने बहुत पैसा भी कमाया था।

बिंद्रा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा, उसने आपराधिक कृत्यों से पैसा कमाया है। मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत वह प्रथम दृष्टया दोषी है। मामले की जांच महत्वपूर्ण स्थिति में है और इस समय बिंद्रा को जमानत दी जाती है तो वह इसे बाधित कर सकता है। चूंकि वह जांच के तरीकों से अवगत है, ऐसे में वह अन्य संदिग्ध लोगों को गिरफ्तारी से बचने में मदद कर सकता है। ईडी ने बिंद्रा के अलावा अब तक हारून अलीम यूसुफ, हुमायू मर्चेंट और रिंकू देशपांडे को गिरफ्तार किया है।

कह के रहेंगे माधव जोशी